भारत सरकार
विदेश मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 849
26.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव

849. श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चीन के वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर सरकार का मौजूदा रुख क्या है;

(ख) क्या सरकार दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में आर्थिक विकास परियोजनाओं को एक विदेश नीति उपकरण के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना निवेश करने की योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो बीआरआई की आर्थिक और विदेश नीति प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत के रणनीतिक एशियाई और अफ्रीकी भागीदारों के बीच क्या रणनीति मौजूद है?

उत्तर
(विदेश राज्य मंत्री)
(श्री वी. मुरलीधरन)

(**क**) चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' (ओबीओआर) अथवा 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (बीआरआई) के संबंध में भारत सरकार का पक्ष स्पष्ट एवं दृढ़ रहा है। एक फ्लैगशिप परियोजना के रूप में 'ओबीओआर/बीआरआई' को तथाकथित 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (सीपीईसी), जो पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरता है, को शामिल किया जाना भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता संबंधी चिंताओं की अनदेखी को दर्शाता है। सरकार ने चीनी पक्ष को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में की जा रही गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है और उनसे इन गतिविधियों को बंद करने का आग्रह किया है।

संपर्क व्यवस्था का विस्तार एवं इनका सुदृढ़ीकरण भारत की आर्थिक तथा राजनयिक पहलों का एक अभिन्न हिस्सा है। साथ ही सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि संपर्क व्यवस्था संबंधी पहल अवश्य ही वैश्विक रूप से मान्य अंतरराष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होनी चाहिए। इनका अनुसरण खुलेपन, पारदर्शिता तथा वित्तीय जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए और इसे इस प्रकार आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि राष्ट्रों की संप्रभुता, समानता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो सके।

(ख) से (घ) भारत का एक सुदृढ़ विकास सहयोग एजेंडा है जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के साथ-साथ अनेक सहभागी देशों के साथ घनिष्ठ एवं बहुआयामी संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम शामिल है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के विविध क्षेत्रों, जैसे विद्युत, परिवहन, संपर्क व्यवस्था, कृषि तथा सिंचाई, विनिर्माण उद्योग, जल तथा स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल आदि में रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला का विस्तार इस विकास भागीदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है।

भारत सरकार की ऋण श्रृंखला के एक हिस्से के तौर पर एशिया, अफ्रीका, लातिन अमरीका, कैरीबियाई देश, ओसियानिया तथा स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के 63 देशों को लगभग 28 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली 279 ऋण श्रृंखलाएं प्रदान की गई हैं। इनमें से 4.70 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली 254 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जबकि 19 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत वाली 194 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इनमें भारत के निकटतम पड़ोस में स्थित 5 देशों में 94 कनेक्टिवटी परियोजनाएं शामिल हैं जो लगभग 6.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण श्रृंखला की सहायता से लागू की जा रही हैं।

***